pooled from the fee should meet, at least, 20 per cent. But realising that the accessibility is very important, there is still a debate on whether the fee should be high or whether it should be retained at whatever level it is. But accessibility has always been a priority with the Government of India.

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बकाया राशि की वसूली

*242. डा॰ मुरली मनोहर जोशी:

श्री रवि शंकर प्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिजली उपभोग की राशि गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा कमीशन देकर वसूल कराए जाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना कतिपय राज्यों में पहले से ही लागू है, यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) यह योजना लागू करने के संभावित लाभ क्या-क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विद्युत अधिनियम की धारा 14 परंतुक (vii) में अपनी ओर से वितरण व्यवस्था करने के लिए वितरण लाइसेंसियों द्वारा फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति की व्यवस्था है।

(ख) यूटिलिटियां राजस्व आधारित फ्रैंचाइजियों (मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रह के लिए) से लेकर इनपुट आधारित फ्रैंचाइजियों (राजस्व संग्रह, प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए उत्तरदायी) की नियुक्ति के विभिन्न मॉडल अपना रही है।

(ग) 14 राज्यों नामशः उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, नागालैंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति की सूचना दी है।

(घ) विद्युत क्षेत्र की फ्रैंचाइजी प्रणाली के संभावित लाभ निम्नानुसार हैं—

(i) उपभोक्ता सेवाओं में सुधार;

(ii) राजस्व संग्रह को बढ़ावा;

(iii) एकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी;

(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के बेहतर राजस्व निरंतरता के लिए कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के उत्पादी भार का ह्रास।

Collection of electricity dues in rural areas

†*242. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:††

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has formulated a scheme to charge the bill amount for electricity consumption from the rural consumers in the country by paying commission to non-Government institutions to charge the same;

†Original notice of the question was received in Hindi.
††The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravi Shankar Prasad.

(b) if so, the details of the said scheme;

(c) whether this scheme is already in force in certain States, if so, the names of such States; and

(d) what are the likely benefits of implementing this scheme?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Section14 proviso (vii) of Electricity Act 2003, provides for appointment of franchisees by distribution licensees to undertake distribution on their behalf.

(b) Various models for appointment of franchisees are being followed by utilities, ranging from revenue based franchisee (for undertaking metering, billing and collection) to input based franchisee (responsible for revenue collection, operation and maintenance and improvement of service to consumers).

(c) 14 States have reported appointment of franchisees, namely, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka. Bihar, Orissa, Chhattisgarh, Gujarat, Assam, Nagaland in rural areas.

(d) The likely benefits of the franchisee system to the power sector are:

(i) Improvement in consumer services;

(ii) Enhancement in revenue collection;

(iii) Reduction in Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses; and

(iv) Development of productive loads of agriculture and rural industry for better revenue substainability of rural electrification, etc.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उसको देखने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि यह तो हम सबों की जानकारी में है कि विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत franchisee की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन आपके उत्तर से जो एक बहुत रोचक बात दिखाई पड़ती है, वह यह है कि यह नियुक्ति जिन प्रदेशों में हो रही है वह राजनीतिक रंग से निरपेक्ष है। इसमें कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं, भाजपा शासित प्रदेश भी हैं, वामपंथी शासित प्रदेश भी हैं, तो यह जो नई सुधार की प्रक्रिया है, इसका परिणाम जमीन पर दिखाई पड़ रहा है । आपने अपने उत्तर के पैराग्राफ "डी" में यह कहा है कि इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं —Improvement in consumer services and enhancement in revenue collection. अच्छा होता, अगर आप अपने उत्तर में जमीन पर इस वसूली का कैसा अनुभव आ रहा है, इसके प्रतिशत से इस सदन को अवगत कराते। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना इसलिए जरूरी समझता हूं कि दिल्ली में भी collections को outsource किया गया है और यहां दिल्ली में अपने उपभोक्ताओं का अनुभव बहुत संतोषजनक नहीं है अगर दिल्ली जैसे देश की राजधानी में विद्युत के उपभोक्ताओं को यह परेशानी हो रही है, तो जमीन पर जो गरीब किसान हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, यह हम जानना चाहते हैं? इसलिए इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में इस नए सुधार से क्या परिणाम निकला है, कृपया यह बताने की कृपा करें?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य से जो प्रश्न पूछा है, वह ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में है। जो भी जानकारी उनको चाहिए, वह मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आप दिल्ली के बारे में कह रहे हैं और दिल्ली अर्बन एरियाज में आती है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रूरल एरियाज में, आरजीजीवाई में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसमें कानून में ही फ्रेंचाइजिज का प्रावधान है और इस प्रावधान के माध्यम से अभी 14 राज्यों में फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू हो गया है। बीच में हमने टेरी और इरादे की जो संस्थाएं हैं, उनसे रिसर्च करवा कर कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि हमारी यह योजना किस तरह चल रही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में यह योजाना इन्पुट बेस्ड नहीं है, वहां फ्रेंचाइजी रेवेन्यू कलेक्शन बेस पर है। वहां 131 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि काम करते हैं और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वहां पर रेवेन्यू में 130% का इन्क्रीज हुआ है।

अभी यह योजना 14 राज्यों में चल रही है। उत्तराखंड में भी इससे प्रॉफिट हो रहा है। उसके सभी फिगर्स मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें बताने में मैं सभागृह का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। यह योजना वहां पर बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यह केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण भू-भागों में इससे काफी रोजगार भी मिल रहा है। हमारे पास ऐसी जानकारी भी है और हम देख भी रहे हैं, कि वहां पर फ्रेंचाइजिज में एक्स सर्विसमैन, विधवाओं और युवकों को भी रोजगार मिल रहा है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने दिल्ली के बारे में भी पूछा था, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अब दिल्ली भी प्रॉफिट में आ रही है। फेंचाइजिज में दिल्ली भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां चोरियां होती हैं, उनके परिणाम को अभी भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते है कि जैसे सूरत में अच्छा काम हुआ है, भिवंडी में अच्छा काम हुआ है, अहमदाबाद में अच्छा काम हुआ है, दिल्ली में भी उसी तरह काम हो। महाराष्ट्र में जो भिवंडी गांव है, वहां बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में वहां कोशिशें कर-कर के थक गई थी, लेकिन फ्रंचाइजिज को देने के बाद, छ: महीने में वहां 20% चोरी कम हो गई है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैंने दिल्ली का संदर्भ एक विशेष उद्देश्य से दिया था और वह इसलिए दिया था कि दिल्ली में इस तरह से फ्रेंचाइज कलेक्शन में उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही हैं अगर देश की राजधानी में कठिनाई हो रही है तो गांव में, साधारण गरीब किसानों को कठिनाई न हो, इस संदर्भ में मैंने आपको यह बात कही थी और आपने इसे स्वीकार किया था।

आपने अपने उत्तर के पैराग्राफ 'बी' में दो मॉडल्स की बात कही है। एक रेवेन्यू मॉडल है और एक इनपुट मॉडल है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि ये मॉडल तैयार कौन करता है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि फेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसैंस क्या आप लोग केवल अपने सब-कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं अथवा इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्रामीण संस्थाओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: फेंचाइजिज की कल्पना ही इस चीज को लेकर है कि ग्रामीण उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले। इसमें ग्राम पंचायत है, सोसाइटीज हैं, इंडीवीज्वल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, साथ ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं। उन्हें भी यह काम दिया जा रहा है और उत्तराखंड में तो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मॉडल बन गया है उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि उसी मॉडल को हम पूरे देश में बना रहे हैं।

यह बात सही है कि एक साल पहले जब हमने इसका रिव्यू लिया तो हमारी नजर में यह बात आई कि हमने इसकी ट्रेनिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया था। इसलिए इसके अन्दर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए मैंने स्वयं कहा है। यह काम पूना में जो यशदा है, वहां हो रहा है और साथ ही टिहरी में भी हो रहा है, ताकि वे ट्रेन्ड हो कर फेंचाइजी को भी ट्रेन्ड कर दें कि किस तरह एकाउंट रखा जाए, कैसे बिजली दी जाए, कैसे कनैक्शन दिए जाएं और किस तरह वह अपनी एकाउंटेबिलिटी रखे। यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ही चल रही है। आपने अपना प्रश्न पूछते समय शायद इस योजना का नाम नहीं लिया है, मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से ही इसकी शुरूआत हो गई है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि आज हमारे पास जिन 14 राज्यों में यह फेंचाइजिज का काम हो रहा है, वहां नागालैंड तक सभी जगह से हमें यह जानकारी मिली है कि काम अच्छी तरह से हो रहा है। देहातों में यह काम शुरू होने से जो चोरी करने वाले लोग हैं, उन पर भी कंट्रोल किया जा सका है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, आप किसी का नाम रखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 5 हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, उनका सदुपयोग होना चाहिए।

श्री सुशल कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, यह केवल 5 हजार करोड़ रुपए की बात नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि यू॰पी॰ए॰ सरकार का यह वादा है तथा देश को प्रधान मंत्री और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यू॰पी॰ए॰ सरकार ने बताया है कि पूरे देश में ...(व्यवधान)... पूरे देश को बताया है कि 1 लाख 25 हजार गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लेकिन जब सदन में मांग आ गई थी कि 3000 हेबिटेशन की लिमिट को जरा कम कर लिया जाए, तो हमने यह काम किया है। हमने इस पर ध्यान दिया है। हम इसमें अभी 300 के बजाए 100 हैबिटेशन पर आ

गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो नई डिफिनेशन आई है, उससे इसमें 1 लाख 34 हजार 246 विलेजेज हो जाएंगे, जो पहले 1 लाख 20 हजार थे। सम्मानीय सदस्य को यह मालूम होने पर बहुत खुशी होगी कि जितने ज्यादा लोग हैं, उनको हम बिजली देने का काम देश में कर रहे हैं।

DR. K. MALAISAMY: Mr. Chairman, Sir from the reply of the hon. Minister, it is seen that there are more advantages in the appointment of franchisees. I am inclined to ask him: What are the disadvantages in the system? A cuplet* in Tamil in Thirukkural means that if we want to decide an issue, we have to see what the various advantages and disadvantages of it are, and whichever is more the issue has to be decided on that basis. The hon. Minister has said that 14 States are following the franchieese system. In such a situation, I feel that there must be some minus points in the system, and that is why, the other States have not followed it. If the advantages are more, the other States also should have followed it. What exactly is the reason?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, the other States are also following it. Even Kerala and Tamil Nadu have been in line with that because everyone likes this idea of franchisees. And, as the hon. Member has asked about disadvantages, there is only one disadvantage, that is, they do not become partner in losses. They only get commission on input base, or, on billing base, whatever way it is. But I must tell you that this is the beginning of the scheme. And, I, personally, feel that there may ot be much disadvantage in the scheme because more and more States are coming in line with this. It is true that the hon. Member's point is on bifurcation of the utility, the Electricity Board. Yes; wherever utility has been bifurcated, it has been proved—I am not using the word 'disbandment'; I have said, 'bifurcation'— the losses have come down in that utility, and the financial position of the utility has improved.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहता हूं। अपने उत्तर में मंत्री जी ने जो लाभ गिनाए हैं, उनमें उनका कहना है कि उपभोक्ता सेवाओं में वृद्धि होगी, बकाया वसूली तेजी से हो जाएगी, चोरी पर रोक लगेगी तथा कृषि और ग्रामोद्योगों का तेजी से विस्तार होगा। यह फ्रेंचाइजी देने से आपने ये सारे लाभ यहां पर बताए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को केवल यह जानकारी दे दूं वैसे वह उनको होगी भी कि 80 के दशक में केन्द्र सरकार ने एक योजना बनाई थी, इन्हीं लक्ष्यों को रख कर, जिनका आपने जिक्र किया है और उसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतों में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां बनाई गई थीं। ये ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां अनेक प्रदेशों में अनेक वर्षों से काम कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, इसलिए वहां की बात पूछ सकता हूं, बाकी प्रदेशों का भी हाल लगभग वही होगा, क्या वह मुझे यह जानकारी देंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का गठन किया गया था और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इतने वर्षों बाद उन में से कौन-सी एक भी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति ऐसी है, जो आज लाभ में चल रही हो, जिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के विस्तार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो और जिस की वसूली पूरी हो रही हो? ऐसे लक्ष्य जो आप ने यहां रखे हैं, उन को प्राप्त करने के मामले में मध्य प्रदेश की कौन सी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति आपके पैमाने पर खरी उतरी है, मंत्री जी, हमें उसका नाम बता दें?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, वर्ष 1980 की मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आज नहीं हैं। सम्मानित सदस्य शायद कुटीर योजना के बारे में कहते होंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मेरा कहना यह है कि 1980 से आज तक वे ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां अनेक प्रदेशों में आज भी काम कर रही हैं और यही लक्ष्य जो आप ने यहां बताए हैं, यही लक्ष्य उनके सामने भी रखे गए थे और उनके पीछे भी यही उद्देश्य था।

श्री सभापति: आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: अभी नयी योजना बनायी है और यह पहले के अनुभव को देखते हुए बनायी हैं उसमें तो कभी 50 परसेंट सब्सिडी देने की बात थी, कभी वह 40 परसेंट थी और कभी राज्यों ने 60 परसेंट पैसा भरना था। वह सक्सेसफुल नहीं हुई, जिस वजह से यू॰पी॰ए॰ गवर्नमेंट जैसे ही सत्ता में आई, उस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह कार्यक्रम लिया कि देश को बिजली देना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और ग्रामीण जीवन में लोगों को बिजली देना विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा निर्णय लिया गया और देश के 1 लाख 34 हजार गांवों को बिजली देने का निर्णय ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister finish, please.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: No, no. It has nothing to do with that. 1 लाख 34 हजार गांवों को बिजली देने का तय किया है और इस योजना में 90 परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इस के लिए राज्यों का 10 परसेंट जो लोन है, वह भी 20 साल में वापिस करना है, सर, इतनी अच्छी योजना पहले नहीं थी। सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हो गया है, यदि वह मुझे लिखकर दे दें तो मैं इंक्वायरी करवा लूंगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, सवाल यह है कि जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि ये ग्रामीण समितियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी हैं, असफल हो गयी हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि फिर इन ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को बनाए रखने की वजह क्या है, औचित्य क्या है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: अभी वे समितियां नहीं, वह सिस्टम अलग है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: वे समितियां आज भी काम कर रही हैं, पता कर लीजिए।

MR. CHAIRMAN: Please go ahead.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir. we are very pleased that the Government has taken steps to improve consumer services in the power sector. But I am sorry to state that there are various problems being faced by the consumers in Assam. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is aware of the fact that people in Assam are suffering tremendously owing to excess billing due to faulty electronic metres. I would also like to know whether your Ministry can solve these types of problems and take steps to improve consumer services in Assam.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Mr. Chairman Sir, It has been reported by some States that there are faulty meters. We have asked those Governments and utilities to correct them immediately. But, in Assam, the situation is quite good. The revenue collection has increased to 89 per cent there. I have not received any complaint from Assam in this regard. But as far as the excess billing is concerned. I would certainly issue directions to the State Government or the utility to look into this matter.

(Q.No. 243—Hon. Members absent.)

*[The questioner(s) Shri Santosh Bagrodia and Shri Kalraj Mishra were absent. For answer *vide* page 17 infra.]

वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि किया जाना

*244. **श्रीमती प्रेमा करियप्पा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों और विशेषकर कर्णाटक में वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और